निज़ाम और अन्य.

बनाम

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 413/2007)

सितम्बर 04, 2015

[दीपक मिश्रा और आर. भानुमति, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860- एस.एस. 302 एवं 201 - के तहत अभियोजन - परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर - निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - अपील पर, निर्णित हुआ: परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराध स्थापित करने के लिए परिस्थितियो को मजबूती से स्थापित किया जाना चाहिए और परिस्थितियों की श्रृंखला तथ्यों की दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए - अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियां हैं - मामले के तथ्यों में, परिस्थितिओं की श्रृंखला पूर्ण नहीं थीं जिससे केवल अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित किया जा सके और कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सके- यदि इससे अधिक हो एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो आरोपी को सन्देह का लाभ मिलना चाहिए - इसलिए, अपीलकर्ता/अभ्युक्तों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता - साक्ष्य - परिस्थितिजन्य प्रमाण।

साक्ष्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - 'अंतिम बार देखा गया सिद्धांत' - की प्रयोज्यता - माना गया: सिद्धांत को अभियोजन पक्ष के मामले को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए, पिछली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अंतिम बार देखे जाने वाले के बिन्दु का पालन करते हुए - केवल अगर अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि मृतक को आखिरी बार आरोपियों के साथ जीवित देखा गया था, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब भार आरोपी पर स्थानांतरित किया गया हो। केवल 'आखिरी बार देखे गये सिद्धांत'' के आधार पर दोषसिद्धि करना विवेकपूर्ण नहीं है ' - जहां मृतक को अंतिम बार देखा गया और उसके शरीर की बरामदगी के बीच का समय अंतराल लंबा है, वहां बिना देखे दोषसिद्धि का आधार बनाना असुरक्षित होगा - अन्य परिस्थितियोें और साक्ष्यों से पुष्टि- साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106।

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद. 136 - के तहत क्षेत्राधिकार - माना गया: आम तौर पर, समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है - लेकिन जहां भौतिक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है और जहां अदालतों के निष्कर्ष साक्ष्यों के आधार पर असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्याय में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसी अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप की अनुमति है।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :

1.1 अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकला जाता है उन्हें पूर्णतः सिद्ध किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ एक श्रृंखला बनाते हुए पूर्ण होनी चाहिए, और साक्ष्यों की शृंखला में कोई अन्तराल नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए जो उसके साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत हो। [पैरा 8] [794-डी-ई]

बोधराज उर्फ बोधा और अन्य। बनाम जम्मू राज्य और कश्मीर 2002 (2) पूरक। एससीआर 67: (2002) 8 एससीसी 45; त्रिमुख मारोती किरकन बनाम राज्य महाराष्ट्र 2006 (7) सप्ल. एससीआर 156: (2006) 10 एससीसी 681;सुनील क्लिफ़ोर्ड डेनियल बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब 2012 (7)एससीआर 1100: (2012) 11 एससीसी 205; संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, कृष्णागिरी 2012 (2) एससीआर 289: (2012) 4 एससीसी 124; मो. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) 2011 (10) एससीआर 56: (2011) 13 एससीसी 621- पर भरोसा किया गया।

1.2 निचली अदालतों ने पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया कि मृतक को आखिरी बार 23.01.2001 को अपीलकर्ताओं के साथ जीवित देखा गया था। निश्चित रूप से, "अंतिम बार देखा गया सिद्धांत" परिस्थितियो की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और साक्ष्य के बोझ को स्थानांतरित करने के लिए अदालतें अभियुक्त पर दबाव डालती हैं और अभियुक्त को मृतक की मृत्यु के कारण का उचित स्पष्टीकरण देने का प्रस्ताव देती हैं। केवल "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" पर दृढ़विश्वास को दोषसिद्धि का आधार बनाना विवेकपूर्ण नहीं है "अंतिम बार देखे गये सिद्धांत" को अभियोजन पक्ष के मामले को सम्पूर्णता में ध्यान में रखते हुए और अंतिम बार देखे जाने से पहले और बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। [पैरा 14] [797-एच; 798-ए-सी]

राजस्थान राज्य बनाम काशी राम 2006 (8) पूरक। एससीआर 501: (2006) 12 एससीसी 254; किरीती पाल बनाम राज्य पश्चिम बंगाल (2015) 5 स्केल 319 - संदर्भित।

1.3 केवल यदि अभियोजन पक्ष निश्चित साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित करने में सफल रहा हो कि मृतक को आखिरी बार अभियुक्त की संगति में जीवित देखा गया था, तो आरोपी के खिलाफ एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है और केवल तभी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के

तहत अभियुक्त पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है. [पैरा 16] [799-एफ-जी]

1.4 जहां समय अंतराल लंबा है, वहां "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" पर दृढ़ विश्वास का आधार बनाना असुरक्षित होगा; अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों से पुष्टि की तलाश करना अधिक सुरक्षित है। तथ्यों और साक्ष्य से, अंतिम बार देखे गए सिद्धांत की पुष्टि करने वाला कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला है। जब मृतक ट्रक में गया था और उसके शव की बरामदगी के बीच के अंतराल को ध्यान में रखते हुए और उस स्थान और उन परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए जहां शव बरामद हुआ था, अन्य लोगों के हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। निश्चित सबूतों के अभाव में इस बात के आधार पर कि अपीलकर्ता और मृतकों को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और जब समय अंतराल लंबा हो, तो इस निष्कर्ष पर आना खतरनाक होगा कि अपीलकर्ता हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। [पैरा18] [800-डी-एफ]

1.5 वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के कब्जे से न तो हत्या का कोई भी हथियार न ही अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से लूटा गया धन या कोई अन्य सामग्री बरामद की गई। जांच में कई स्पष्ट खामियां हैं और और कड़ियां गायब हैं - (i) चुराये गये धन की वसूली न होना; (ii) वह हथियार

जिससे खरोंचे आई हों; (iii) पीडब्लू-2 द्वारा झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप कि उसे कुछ अन्य बदमाशान द्वारा लूटा जा रहा था; (iv) शव की पहचान न होना और (v) इसका कारण स्पष्ट किया गया है कि मृतक उस गांव में कैसे पहुंचा, जहां उसका शव और आंतरिक अंग (लिंग) पर चोट के निशान मिले । इस प्रकार, अभियोजन के मामले में कई खामियां हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराध स्थापित करने के लिए परिस्थितियों को मजबूती से स्थापित किया जाना चाहिए और परिस्थितियों की श्रृंखला को तथ्यों से पूरा किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला के आधार पर किसी भी तरीके से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। [पैरा 19] [800-जी-एच; 801-ए-सी]

1.6 पीडब्लू 1 और 2, के साक्ष्य के आधार पर निचली अदालतों ने यह विचार व्यक्त किया गया है कि मृतक की हत्या का मकसद पैसों की लालसा थी जो वह था ले जा रहा था। निचली अदालतों ने अपीलार्थियों की सजा को पीडब्लू 1 और 2 द्वारा बतायी गयी परिस्थितियों "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" के रूप में तथा साथ ही पीडब्लू-6 द्वारा रसीद और बिल्टी की वसूली पर आधारित किया है जिस पर अभियुक्त का नाम मुद्रित किया गया था लेकिन अपीलकर्ताओं न तो 20,000/- रु. और न ही इसका कोई हिस्सा बरामद किया गया। यदि अभियोजन पक्ष अपने मामले को मकसद के आधार पर साबित करने में सक्षम है तो यह अभियोजन मामले को

आश्वासन देने वाला एक पुष्टिकारक साक्ष्य होगा। लेकिन भले ही अभियोजन पक्ष मकसद को साबित नहीं कर पाया हो परन्तु यह अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होगा। मकसद के साक्ष्य की अनुपस्थिति केवल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच और गहन विश्लेषण की मांग करती है। अपीलकर्ताओं से राशि की वसूली नहीं होने के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित मकसद पर भी गंभीर संदेह पैदा होता है। [पैरा 12 और 13] [797- बी-एफ]

1.7 अभियोजन द्वारा विश्वास किए गए और निचली अदालतों द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी परिस्थिति को केवल अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इंगित करते हुए नहीं कहा जा सकता है और जिससे कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।यदि एक से अधिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तो अभियुक्त को संदेह का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता। [पैरा डी 20] [801-ई-जी]

2. सामान्यतः यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दिये गये समवर्ती निष्कर्षों के साथ अपनी शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जहां भौतिक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है और जहां न्यायालय के निष्कर्ष परिणामी रिकार्ड पर साक्ष्य के

आधार पर अप्रमाणित हैं जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, यह न्यायालय निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। [पैरा 20] [801-डी-ई]

केस कानून संदर्भ

2002 (2) पूरक एससीआर 67	पर भरोसा किया।	पैरा 9
2006 (7) पूरक एससीआर 156	पर भरोसा किया।	पैरा 10
2012 (7) एससीआर 1100	पर भरोसा किया।	पैरा 10
2012 (2) एससीआर 289	पर भरोसा किया गया।	पैरा 10
2011 (10) SCR56	पर भरोसा किया।	पैरा 10
2006 (8) पूरक एससीआर 501	का उल्लेख किया गया।	पैरा 15
(2015) 5 स्केल 319	का उल्लेख किया गया।	पैरा 15

आपराधिक अपीलीय न्यायक्षेत्र: आपराधिक अपील क्रमांक 413/2007।

राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर बेंच की आपराधिक अपील संख्या 1248/2002 में,पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.07.2005 से।

शेखर प्रीत झा (ए.सी.)। विक्रान्त भारद्वाज अपीलकर्ताओं की ओर से।

राम नरेश यादव, मिलिंद कुमार, सुनील कुमार शर्मा प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश आर. भानुमति, जे. द्वारा पारित किया गया:-

1. यह अपील 2002 की आपराधिक अपील संख्या 1248 में राजस्थान उच्च् न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 01.07.2005 को पारित फैसले की सत्यता पर सवाल उठाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आरोपी की सजा की पुष्टि की थी। अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गयी और प्रत्येक को धारा डिफॉल्ट धारा के साथ 2,000/- रुपये का जुर्माना और साथ ही डिफाल्ट धारा के साथ 500/- रूपये के जुर्माने के साथ दो वर्ष का कठोर कारावास भी दिया गया।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक-मनोज ट्रक क्रमांक एमपी-07-2627 पर हेल्पर था और अपने पहले ड्राइवर राज कुमार(पीडब्लू-2) और दूसरे ड्राइवर राम प्रकाश (पीडब्लू-1) के साथ पुणे और उसके बाद बरार गया था और बरार से उन्होंने 23.01.2001 को गाजियाबाद तक गंतव्य के लिए ट्रक में पाइप लोड किए। अभियुक्त-अपीलकर्ता निज़ाम और शफीक जो ट्रक संख्या डीएल-1 जीए-5943 पर क्रमशः ड्राइवर और क्लीनर थे, ने भी उसी दिन बरार में अपने ट्रक में उसी कंपनी के पाइप लोड किये और ट्रक नंबर एमपी-07-2627 के साथ गाजियाबाद चल दिये।इस अवधि के दौरान दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर में एक दूसरे के साथ जान-

पहचान हो गई। गाजियाबाद जाते समय ट्रक क्रमांक एमपी-07-2627 के ड्राइवर राजकुमार (पीडब्लू-2) का कुछ स्थानीय व्यक्तियों से झगड़ा हो गया और परिणामस्वरूप बरार पुलिस ने ट्रक सहित उसे हिरासत में लिया। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए राज कुमार (पीडब्लू-2) ने अपने दूसरे ड्राइवर राम प्रकाश (पीडब्लू-1) को ट्रक मालिक को पैसे देने के निर्देश के साथ 20,000/- रुपये की राशि मनोज को सौंपने का निर्देश दिया। तदनुसार, मनोज दिनांक 23.01.2001 को ट्रक क्रमांक डीएल-1 जीए 5943 से आरोपियों को लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हुआ।

3. मृतक-मनोज का शव दिनांक 26.01.2001 को ग्राम मनिया के पास एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। दिनांक 26.01.2001 को लगभग 3.00 बजे, कोके सिंह (पीडब्लू-13) चारा इकट्ठा करने गए और उन्हें एक शव खेत में पड़ा हुआ देखा और इसकी सूचना शहजाद खान(पीडब्लू-4) को दी गई। शहजाद खान (पीडब्लू-4) की लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 26.01.2001 को थाना मनिया, जिला धौलपुर में एफआईआर संख्या 16/2001 धारा 302 व 201 भादंसं के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुल्लू खान (पीडब्लू-16)- जांच अधिकारी ने शव को जब्त कर पंचनामा तैयार किया।मृतक-मनोज के पतलून की जेब से उत्तर प्रदेश, हरियाणा रोडलाइन्स (पुणे) की एक बिल्टी (प्रदर्श. पी17) और ट्रक क्रमांक DL-1GA-5943 से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार, शिवपुरी नाका की एक रसीद (प्रदर्श. पी18) बरामद की गयी और उक्त बिल्टी (प्रदर्श.पी-17)

में चालक का नाम निज़ाम अंकित था और ट्रक नंबर DL-1GA-5943 और कुछ फ़ोन नंबर अंकित थे। बिल्टी से मिले सुराग के आधार पर दिनांक 27.01.2001 को आरोपी निज़ाम और शफीक को गिरफ्तार किया गया था और ट्रक संख्या DL-1GA-5943 बरामद किया गया। उचित जांच के बाद, अपीलकर्ताओं-आरोपियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302 और 201 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

4. अभियुक्त-अपीलकर्ताओं, के अपराध को उजागर करने के लिए अभियोजन पक्ष ने इक्कीस गवाहों से पूछताछ की है।सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी-अपीलकर्ताओं के सामने अभियोगात्मक साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश की गईं और अभियुक्तों ने उन सभी बातों से इनकार किया और अभियुक्तों ने कहा कि मनोज ने कभी भी ट्रक DL-1GA-5943 में यात्रा नहीं की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय नंबर 2, धौलपुर ने माना कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने 20,000/- रुपये हड़पने के लिए मृतक-मनोज की हत्या की और अभियोजन पक्ष ने धारा 302 और 201 भा.दं.सं.के तहत अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषी साबित करने वाली परिस्थितियों को स्थापित किया है और उनमें से प्रत्येक को क्रमशः डिफ़ॉल्ट क्लॉज के साथ रु. 2,000/- के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास और डिफ़ॉल्ट क्लॉज के साथ रु. 500/- के जुर्माने के साथ दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। दोषसिद्धि के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने राजस्थान उच्च न्यायालय के

समक्ष अपील की, जिस पर आपत्ति जताई गई अपील को खारिज कर दिया जिससे अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि हुई और साथ ही उनमें से प्रत्येक पर कारावास और जुर्माना राशि की संबंधित सजा अधिरोपित की गई। व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने यह अपील दायर की है।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने "अंतिम बार देखा गया सिद्धांत" प्रस्तुत किया जो तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि उसमें मनोज के कथित तौर पर अपीलकर्ताओं के साथ जाने की दिनांक और समय को लेकर गंभीर विरोधाभास थे। आगे यह तर्क दिया गया कि 20,000/- रूपये की राशि जो कथित तौर पर मृतक-मनोज द्वारा ली गयी थी अपीलकर्ताओं के कब्जे से बरामदगी नहीं की गयी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, वे दृढ़ता से स्थापित नहीं हैं और परिस्थितियाँ अभियुक्तों के अपराध को स्थाापित करने वाली श्रृंखला को पूर्ण नहीं बनाती और अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फँसाया गया है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान वकील तर्क दिया कि जब मृतक ने अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की संगति में यात्रा की तब उसके पास भारी मात्रा में धन था और अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया है कि मृतक-मनोज को आखिरी बार अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के साथ जीवित देखा

गया था तो यह अभियुक्तों को बताना था कि मृतक के साथ क्या हुआ था और अभियुक्तों की ओर से किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं को उचित रूप से दोषी ठहराया है और आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

8. अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का जो निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूरी तरह सिद्ध किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा सभी परिस्थितियाँ एक श्रृंखला बनाते हुए पूर्ण होनी चाहिए और सबूतों की शृंखला में कोई अन्तराल नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए जो उसके साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत हो।

9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में दोहराया गया है। बोधराज उर्फ बोधा और अन्य बनाम जम्मू

और कश्मीर राज्य, (2002) 8 एससीसी 45, जिसमें इस अदालत ने कई निर्णयों को उद्धृत किया और निम्नानुसार आयोजित किया:-

> "10. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहां अपराध का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की बेगुनाही या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाती हैं। (हुकम सिंह बनाम राज्य राजस्थान (1977) 2 एससीसी 99, एराडु बनाम हैदराबाद एआईआर 1956 एससी 316, ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (1983) 2 एससीसी 330, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी (1985) सप्ल. एससीसी 79, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1987) 1 एससीसी 1 और अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1989 सप्ल.(1) एससीसी 560 देखें) वे परिस्थितियाँ जिनसे आरोपी के अपराध का अनुमान लगाया गया है, को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों से अनुमानित किये जाने वाले प्रमुख तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा होना दिखाया जाना चाहिए। भगत राम बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1954 एससी 621 में यह

निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है परिस्थितियो का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही को नकार दे और अपराधों को किसी भी उचित से परे ले जाये।"

11. हम सी. चेंगा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193 में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ भी दे सकते हैं जिसमें इसे इस प्रकार देखा गया है: (एससीसी पीपी. 206-07, पैरा 21)

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए है और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।"

10. त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य में, (2006) 10 एससीसी 681, इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था की:

"12. हस्तगत प्रकरण में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है घटना अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका है परिस्थितिजन्य पर आधारित किसी मामले में सामान्य सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन परिस्थितियो से अपराध का अनुमान लगाया जाता है उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;कि वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती हों; वह संचयी रूप से ली गई परिस्थितियो की इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से बचना संभव नहीं हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्तों द्वारा किया गया था और उन्हें अभियुक्तों के अपराध और उनकी बेगुनाही के साथ असंगतता के अलावा किसी भी परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए।"

सुनील क्लिफ़ोर्ड डेनियल बनाम पंजाब राज्य, (2012) 11 SCC 205, संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, कृष्णागिरी (2012) 4 एससीसी 124 और मो. आरिफ @अशफाक बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011) 13 एससीसी 621 और कई अन्य निर्णय में भी यही सिद्धांत दोहराए गए थे,.

11. पीडब्लू 1, 2 और 3 की गवाही के अवलोकन से, यह देखा गया है कि PW1-राम प्रकाश और PW2-राज कुमार भी ने मृतक क्लीनर मनोज के साथ अपने ट्रक नंबर एमपी-07-2627 को बरार में पाइपों से लोड किया था और उसी समय आरोपी निज़ाम और शफीक का एक अन्य ट्रक नम्बर DL-1 GA-5943 भी पाइपों से भरा गया था। गाजियाबाद जाते समय रास्ते में झगड़ा हो गया ट्रक क्रमांक एमपी 07-2627 के ड्राइवरों और कुछ स्थानीय व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो गया और राज कुमार (पीडब्लू-2) को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राज कुमार (पीडब्लू-2) ने राम प्रकाश (पीडब्लू-1) को 20,000/- रूपये की राशि मनोज को सौंपने का निर्देश दिया और निर्देश दिया कि यह पैसा ट्रक मालिक को दे दिया जाये और उसे आरोपी निज़ाम और शफीक के साथ दूसरे ट्रक डीएल-1 जीए-5943 में भेज दिया गया। पीडब्लू 1 और 2 ने आगे कहा कि पुलिस स्टेशन से रिहा होने के बाद वे ग्वालियर चले गये और अपने मालिक रजनीश कांत (पीडब्लू-3) से मनोज के बारे में पूछताछ की। जिन्हें मनोज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस दौरान उसकी जेब से बरामद बिल्टी और रसीद पर के आधार पर पूछताछ की गयी। मृतक-मनोज की पतलून, मनिया पुलिस ने पीडब्लू-3 ट्रक के मालिक से संपर्क किया और संपर्क करने पर, पीडब्लू 1 से 3 मनिया थाने जाकर मृतक की पहचान की उसके कपड़ों और तस्वीरों से वह व्यक्ति मनोज जैसा दिखता है।

12. पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य के आधार पर, निचली अदालतों ने यह विचार व्यक्त किया कि मनोज की हत्या का उद्देश्य पैसे की लालसा थी जो मनोज ले जा रहा था। निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं की सजा को पीडब्लू 1 और 2 द्वारा बताये गये "अंतिम बार देखे गये सिद्धांत" की परिस्थितियों के साथ साथ पीडब्लू-6 द्वारा बिल्टी और रसीद की वसूली पर आधारित किया जिस पर आरोपी व्यक्ति (निज़ाम)का नाम मुद्रित था। अपीलकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने उस रकम के लिए मनोज ने मनोज की हत्या की है जो वह ले जा रहा था। लेकिन अपीलकर्ताओं से न तो रु. 20,000/- की राशि और न ही कोई इसका कुछ हिस्सा बरामद किया गया था। यदि अभियोजन पक्ष अपने मामले को मकसद के आधार पर साबित करने में सक्षम है, तो यह अभियोजन मामले को आश्वासन देने वाला एक पुष्टिकारक साक्ष्य होगा। लेकिन भले ही अभियोजन मकसद साबित नहीं कर पाया हो फिर भी, यह अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होगा। मकसद के साक्ष्य का अभाव केवल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच और गहन विश्लेषण की मांग करती है।

13. अपीलकर्ताओं से राशि की वसूली न होने के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। सुदामा विट्ठल दरेकर (पीडब्लू-17) के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ड्राइवर राज कुमार पुलिस स्टेशन में शिकायत करने आया था। दूसरे वाहन वालों में पांच से सात लोगों ने उसे और पैसे लूट लिए हैं। हालांकि,

जांच के बाद पता चला कि राज कुमार ने झूठी सूचना दी थी और उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 182 के तहत मामला दर्ज किया गया। राज कुमार को न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय ने उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।इस तथ्य को जांच अधिकारी पीडब्लू-16 से प्रतिपरीक्षा के दौरान सत्यापित कराया गया।

14. निचली अदालतों ने साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया।पीडब्लू1 और 2 के अनुसार मृतक को 23.01.2001 को अपीलकर्ता के साथ आखिरी बार जीवित देखा गया था। निस्संदेह, "अंतिम बार देखा गया सिद्धांत" है परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी जो कुछ निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करेगी। अंतिम देखा गया सिद्धांत" अदालतों को सबूत के बोझ को अभियुक्त पर स्थानांतरित करने के लिए कहता है और अभियुक्त को मृतक की मृत्यु के कारण का उचित स्पष्टीकरण देने के लिए कहता है। इस न्यायालय द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दोषसिद्धि को केवल "अंतिम बार देखे गये सिद्धांत" के आधार निर्धारित करना विवेकपूर्ण नहीं है।"अंतिम दर्शन सिद्धांत" को अभियोजन पक्ष के मामले को समग्रता से लेते हुए आख़िरी बार देखे जाने के पूर्ववर्ती और बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए।

15. राजस्थान राज्य बनाम काशी राम, (2006) 12 एससीसी 254 में "अंतिम बार जीवित देखे जाने" के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय का विनम्र मत निम्न प्रकार है -

> "23. अधिकारियों से गुणा-भाग करना आवश्यक नहीं है। सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान स्पष्ट है और इसे निर्धारित करने में स्पष्ट है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है उस तथ्य को साबित करने का भार है उस एक व्यक्ति पर है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया है, उसे स्पष्टीकरण देना होगा कि कैसे और कब उसकी संगति से अलग हो गया। उसे एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा जो न्यायालय को संभावित और संतोषजनक प्रतीत हो। यदि वह ऐसा करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपना बोझ उतार दिया है। यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा डाले गये बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामले में यदि अभियुक्त उस पर रखे गए बोझ के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, वह स्वयं

परिस्थितियों की शृंखला में एक अतिरिक्त लिंक प्रदान करता है परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध साबित हुईं। धारा 106 आपराधिक मुकदमे में सबूत का बोझ नहीं बदलता, जो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। यह नियम बताता है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में है और जो उसकी बेगुनाही के साथ संगत किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकता तो अदालत किसी भी स्पष्टीकरण को पेश करने में उसकी विफलता को अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकती है, जो श्रृंखला सिद्धांत को पूरा करती है। जिस सिद्धांत को नैना मोहम्मद, आरई. (एआईआर 1960 एमएडी 218) में संक्षेप में बताया गया है "

उपरोक्त निर्णय पर भरोसा किया गया और किरीटी पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2015) 5 स्केल 319 में दोहराया गया "

16. उपरोक्त के प्रकाश में यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, क्या निचली अदालतें "अंतिम बार देखे गये सिद्धांत" को लागू करने में सही थीं। ऊपर चर्चा किये गये साक्ष्यों से, मृतक-मनोज कथित तौर पर दिनांक 23.01.2001 को ट्रक DL-1GA-5943 में रवाना हुआ। मृतक-मनोज का शव 26.01.2001 को बरामद किया गया

था। अभियोजन पक्ष ने दलील दी है कि आरोपियों को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था लेकिन अभियुक्तों ने कोई प्रशंसनीय, ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मनोज के साथ क्या हुआ था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल यदि अभियोजन निश्चित रूप से तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है कि मृतक को आखिरी बार अभियुक्त की संगति में जीवित देखा गया था तो अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है और और उसके बाद ही जिम्मेदारी को आरोपी पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

17. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनसे पूछताछ के दौरान, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने इस बात से इनकार किया कि मनोज ने उनके ट्रक नंबर DL-1 GA-5943 में यात्रा की थी। जैसा कि पहले देखा गया, मनोज का शव तीन दिन बाद 26.01.2001 को बरामद किया गया था। जिस अन्तराल में उस समय के बीच जब मनोज पर कथित तौर पर ट्रक संख्या डीएल-1 जीए-5943 में जाने का आरोप है और शव की बरामदगी होने के समय में इतनी कमी नहीं है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। इस समय, साक्ष्यों से उभरे एक और पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शहजाद खान (पीडब्लू-4) के अनुसार मृतक का आंतरिक अंग (लिंग) रस्सी से बंधा हुआ था और उसकी नाक से खून बह रहा था। मनिया गांव, जिस स्थान पर मनोज का शव बरामद किया

गया, वह कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए एक उल्लेखनीय स्थान है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से मौज मस्ती के लिए लोग आते हैं।

18. मनोज के ट्रक से रवाना होने और शव की बरामदगी के बीच के समय के अंतर और जिस स्थान और जिन परिस्थितियों में शव बरामद हुआ, उसे देखते हुए, अन्य लोगों के हस्तक्षेप की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। निश्चित साक्ष्य के अभाव में कि अपीलकर्ताओं और मृतकों को अंतिम बार देखा गया था और जब समय अन्तराल लंबा है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक होगा कि अपीलकर्ता मनोज की हत्या के गए जिम्मेदार हैं और मनोज की हत्या करने के दोषी हैं। जहां समय अन्तराल लंबा है वहां अंतिम बार देखे गये सिद्धांत" पर दृढ़ विश्वास का आधार बनाना असुरक्षित होगा; अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों से पुष्टि की तलाश करना अधिक सुरक्षित है। तथ्यों और सबूतों से, हमें अंतिम बार देखे गये सिद्धांत की पुष्टि वाला कोई अन्य पुष्ट साक्ष्य नहीं मिला।

19. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में न्यायालय को संपूर्ण साक्ष्यों की संपूर्णता में जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि साक्ष्य से जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह अभियुक्त का अपराध है। हस्तगत मामले में, अपीलकर्ताओं से न तो हत्या का हथियार और न ही उनके द्वारा कथित रूप से लूटा गया धन या उनके कब्जे से कोई अन्य

सामग्री बरामद की गई।जांच में कई स्पष्ट खामियां हैं और कड़ियां गायब हैं :-(i) चोरी हुए पैसे की बरामदगी न होना ; (ii) वह हथियार जिससे खरोंचे आयी हो; (iii) पीडब्लू-2 द्वारा झूठा मामला दर्ज कराया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे कुछ अन्य बदमाशों द्वारा लूटा गया; (iv) शव की पहचान न होना और (v) इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होना कि मृतक मनिया गांव कैसे पहुंचा और उसके आंतरिक अंग (लिंग) पर चोटें कैसे आईं। इस प्रकार हमें अभियोग पक्ष के इस मामले में कई खामियां मिलती हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराध स्थापित करने के लिए परिस्थितियो को पुख्ता दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए और परिस्थितियों की श्रृंखला तथ्यों से पूरी होनी चाहिए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की शृंखला के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।

20. आम तौर पर, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत निचली अदालतों द्वारा दर्ज किये गये समवर्ती निष्कर्षों के तहत अपनी शक्तियों के अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जहाँ भौतिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है और जहां न्यायालय के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अप्रमाणित हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि होती है, यह न्यायालय निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि "आखिरी बार देखा गया सिद्धांत" निचली अदालतों द्वारा काफी हद तक मापा गया है और उच्च न्यायालय ने

अभियोजन मामले में कई खामियों को दरकिनार कर दिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया और निचली अदालतों द्वारा स्वीकार किए गए कथन को केवल अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इंगित करने वाला नहीं माना जा सकता जिससे और कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलते हों। यदि एक से अधिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ताओं की सजा कायम नहीं रखी जा सकती और अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

21. धारा 302 और 201 भा.दं.सं.के तहत अपील कर्ताओं की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया है और अपील की अनुमति दी गई है। अपीलकर्ता जेल में हैं और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो तुरंत उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी परवेज अहमद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।